have agreed to those proposals. So, we have received such recommendations from that committee.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या इस प्रशिक्षण कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति रिटायर हो चुके है उनकी सेवा से लाभ उठाया जा सकता है, यदि ऐसा हो, तो उसके लिए आप क्या यत्न कर रहे हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। इतना ही नहीं कि जो अभी रिटायर हुए हैं उनकी सेवा से लाभ उठाया जाय बल्कि यह भी कहा है कि जिनकी उम्र ६० वर्ष से ऊपर है वह भी अगर ट्रेनिंग के काम में आना चाहेंगे तो उनको भी हम लेंगे।

Shri Ranga: Is it proposed to take some special steps and give facilities for the displaced goldsmiths so that they may be able to get some training in preparing the new type of jewels and also in getting alternative employment in various other industrial spheres?

Shri Lal Bahadur Shastri: If they want to become doctors or engineers, we shall certainly welcome them.

Shri Ranga: I am talking of the industrial sphere.

Shri S. C. Samanta: May I know whether the remaining recommendations of the Thacker Committee will be considered afterwards?

Shri Lal Bahadur Shastri: Yes, in fact, it is a continuing committee; that is, the Thacker Committee is a continuing committee, and they will be sending up their proposals off and on, and those proposals will certaily be implemented. Of course, Government will have to give their final opinion on the recommendations of the committee, and then they will be implemented.

Dr. Sarojini Mahishi: May I know a reaction of the universities and the reaction of the National Medical Council towards the proposal placed by the Thacker Committee in regard to the reduction of the period of training for medical graduates and also the relaxation of the restrictions on rural service by them?

Shri Lal Bahadur Shastri: So far as doctors are concerned, this recommendation has been agreed to by the Medical Council of India as well as the Ministry of Health and has been communicated to the State Governments and universities and Medical colleges by the Medical Council and the Health Ministry for implementation.

दक्षिण भारत में हिन्दी

+

*१३६. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : **श्री इ० मदुसूदन राव** : }

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य के लिये यदि सरकार ने कोई धनराशि आवंटित की है तो कितनी;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खोलने की प्रस्थापना अभी भी विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या** L. T—863/63]

अध्यक्ष महोदय : इसको अंग्रेजी में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब यह कहा

जाता है कि एक विवरण टेबल पर रख दिया गया है, तो उसको हर एक माननीय सदस्य समझ सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : शिक्षा मन्त्री जी ने संसद् के पिछले अधिवेशन में इस प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि दक्षिण भारत के जितने भी विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिन्दी चल रही है, उनके हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रगति देने के लिए केन्द्रीय सरकार और विचार कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, केरल यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी, इन चार यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देता है । उन में हिन्दी डिपार्टमेंट्स नियुक्त किये गए हैं, उनके लिए और रिसर्च वग़ैरह के लिए ग्राण्ट्स दी जाती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : शिक्षा मन्त्री ने बताया था कि मैसूर राज्य ने गुलबर्गा में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खोलने का अनुरोध किया था और इसी प्रकार की चर्चा आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के लिए भी थी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी तक वे सुझाव विचाराधीन हैं या वे निर्णय की कोटि में पहुंच चुके हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक हिन्दी विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, उस के बारे में विचार किया गया है और यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन से भी मशवरा किया गया था । उसकी राय यह थी कि इस समय वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । इस बारे में मिनिस्ट्री विचार कर रही है । अगर वहां पर कोई हिन्दी माध्यम की संस्थायें खुलें, तो उनको उचित सहायता दी जायगी ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या शिक्षा मन्त्री इस तथ्य से अवगत हैं कि दाक्षिणात्य जनता संस्कृत-परिपुष्ट हिन्दी को भली प्रकार समझती है और इसलिए क्या उन संस्थाओं को इस प्रकार की हिन्दी का प्रचलन करने के लिए सहयोग दिया जायगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, सहयोग देते हैं, मदद करते हैं ।

Shri Narasimha Reddy: In view of Government's intention to spread South Indian languages in the North, are there any proposals to establish a Malayalam University in Calcutta, a Tamil University in UP and a Canarese University somewhere in Rajasthan?

Mr. Speaker: Shri Vasudevan Nair.

Shri Vasudevan Nair: May I know whether all the South Indian States have made Hindi a compulsory subject in schools or whether there is any State which has not done so

Dr. K. L. Shrimali: Except in Madras State, Hindi has been made a compulsory subject in all the States.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, एक ओर जब कि दक्षिण के लोग इस कदर उत्साह से हिन्दी सीख रहे हैं, इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि मद्रास में हिन्दी की जो अनिवार्य परीक्षा ली जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि यह कदम तीन-भाषाई फार्मूले से कहां तक मेल खाता है और क्या मद्रास सरकार को इस के लिए पुनः सहमत कराने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह समाचार सही है और मद्रास सरकार स इस बारे में बातचीत की जायगी ।

Shri Heda: May I know whether the attention of Government has been drawn to the conference of Hindi Pundits or Vidwans in Madras State where they have desired and requested their own State Governments to make Hindi a compulsory subject?

Dr. K. L. Shrimali: I have also read that news.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जिन स्थानों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाती है, चूंकि वहां के नौजवानों को नौकरियों के लिए परीक्षाओं में अंग्रेज़ी में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है, इसलिए वे नौजवान अधिकतर असफल हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न तो इसमें से नहीं उठता है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि जिन विश्वविद्यालयों का अभी माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है और जिन को यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन सहायता दे रहा है, उनको जितनी सहायता दी जाती है, शिक्षार्थियों की हिन्दी की शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा बहुत अधिक होने के कारण वह सहायता पूरी नहीं पड़ती है ? यदि हां, तो उस सहायता को बढ़ाने के विषय में सरकार क्या कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अगर माननीय सदस्य उस स्टेटमेंट को देखें, जो कि टेबल पर रखा गया है, तो वह पायेंगे कि बहुत सी योजनायें हैं, जिन के अन्तर्गत हिन्दी की शिक्षा दी जाती है और हिन्दी का प्रचार हो रहा है । मैं उनको यह भी बताऊं कि भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से टीचर्ज़ कालेजिज़ स्थापित किये गए हैं, जिन में अध्यापकों की ट्रेनिंग हो रही है । वे अध्यापक फिर जाकर हिन्दी की शिक्षा देने में मदद करेंगे ।

श्री त्यागी : माननीय मंत्री एक बात का जवाब नहीं दे सके हैं । उस का जवाब दे दिया जाए ।

My hon. friend had enquired what steps Government were taking to encourage South Indian languages in the North.

Mr. Speaker: That was not relevant to this question.

Dr. M. S. Aney: On a point of order, Sir. Can a question be asked partly in English and partly in Hindi.

Mr. Speaker: We are evolving a new language here?

Shri Hari Vishnu Kamath: Composite language?

सीमित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा

+

*१३७. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या गृह-कार्य मंत्री २१ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा कराने की योजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : योजना अभी विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस प्रश्न का पहली बार जो उत्तर दिया गया था, वह लगभग छः मास पूर्व दिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय होने में इतनी देरी क्यों हो रही है और इस बीच में कौन सी खास अड़चनें सामने आई हैं ।

श्री हजरनवीस: देरी इस लिए हुई है कि प्रान्तीय सरकारों से इस बारे में विचार-विमर्श करना पड़ता है और उन की भी सलाह लेनी पड़ती है । कई प्रान्तीय सरकारों ने इस का विरोध किया है । अगर उन सब की सलाह से योजना बनानी है, तो ज़रूर देरी लगेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी बता [illegible] कन किन राज्यों ने